सुमेर सिंह

बनाम

सूरजभान सिंह और अन्य

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 942)

05 मई, 2014

[न्यायाधिपति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और न्यायाधिपति दीपक मिश्रा, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 136-अपील के लिए विशेष इजाज़त याचिका-एक पीड़ित पक्ष विशेष अनुमति याचिका के द्वारा अपील दायर कर सकता है और अनुच्छेद 136 के द्वारा सर्वोच्य न्यायलय के पास विस्तृत शक्तिया है जिसके तहत जब तथ्य और पारिस्थिति वारंट हो तो यह पर्याप्त कारावास आरोपित करता है तथा अन्याय को दूर करता है- दंड प्रक्रिया की धारा, 1973-377(3)

अपीलः

राज्य के द्वारा सजा बढ़ाने के लिए द्वारा आपराधिक अपील- निर्णय :- ऐसी अपील में अभियुक्त अपने बरी होने का अनुरोध कर सकता है। जब उसकी दोषसिद्धि के लिए कोई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड नहीं है।

आपराधिक कानून;

व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार- एक भूमि विवाद के ऊपर पीड़ित का हाथ काट दिया गया। निर्णय: व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग यद्यपि 313 के बयान में विशेष रूप से भी नहीं लिया गया, इसे हमेशा तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है। वर्तमान मामला में, अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय के द्वारा निष्कर्ष को वापस लिया गया है कि घटना के दिन विवादित भूमि का कब्जा पीड़ित और अन्य लोगों के साथ था, और अभियुक्त को उन्हें जबरन बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा, जब अभियुक्त हथियारों से युक्त होकर जब हमला किया, तब पीड़ित हथियारों से युक्त नहीं थे तथा शांति सें अपनी कृषि गतिविधियों को कर रहे थे। हमलावर पर चोटें साधारण प्रकृति थी:- इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि बचाव पक्ष निजी प्रतिरक्षा स्थापित करने में सक्षम नहीं है और न ही उक्त अधिकार के दायरे से बाहर जाने का प्रश्न उत्पन्न होता है।

दंड संहिता, 1860:

धारा 326, 307 और 323/149- भूमि के विवाद के ऊपर अभियुक्त के द्वारा पीड़ित पक्ष को गंभीर चोटे कारित की- पीड़ित पक्ष की कलाई काट दी गई- धारा 307 आईपीसी के अन्तर्गत जुर्माना के साथ 5 साल का कठोर कारावास और आई. पी. सी. की धारा 326 के तहत जुर्माने के साथ

4 साल का कठोर कारावास- उच्च न्यायालय ने अपील में आईपीसी की धारा 326 में दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन सजा की अवधि कम किया जो पहले से भुगत चुका है यानी 7 दिवस- निर्णय: उच्च न्यायालय द्वारा सजा को कम करने का कोई कारण नहीं बताया गया है- अपराध जिस तरीक़े से कारित किया गया वो वह उसकी क्रूरता के बारे में स्पष्ट रूप से बोलता है- एक युवक का हाथ की कलाई को काट दिया गया- जिस तरह से अपराध किया गया वह इसकी क्रूरता के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है- प्रासंगिक समय पर समाज में जो भय मनोविकार व्याप्त था, उसे समझना होगा- उच्च न्यायालय सज़ा की अवधि कम करते समय, यानी जो की 7 दिन की थी, इन पहलुओं पर विचार करने में विफल रहा और संभवतः महसूस किया कि जुर्माना राशि में वृद्धि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगी- जुर्माना राशि में वृद्धि या मुआवजे का अनुदान संहिता के तहत कानून में उचित उत्तर नहीं होगा- स्पष्ट रूप से अपर्याप्त और अनुचित सजा में हस्तक्षेप करना उचित है, क्योंकि न्यायालय पीड़ित की पीड़ा और पुकार पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है। समाज इसलिए, संतुलन बनाते हुए, न्याय का उद्देश्य सबसे अच्छा होगा यदि प्रत्यर्थी-अभियुक्त को ट्रायल जज द्वारा लगाए गए जुर्माने के अलावा दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाए।

सजा को कम करना- उच्च न्यायलय के द्वारा 5 साल की कठोरतम सज़ा को पूर्व में भुगती हुई सजा के अनुसार काम किया यानी 7 दिन तथा

ज़ुर्मान की राशि को बढ़ाया दिया। निर्णय: हालाँकि सज़ा का प्रश्न विवेक का विषय है, फिर भी उक्त विवेक का उपयोग अदालत के द्वारा काल्पनिक और मनमौजी तरीके से नहीं किया जा सकता है- उक्त विवेक को लचीले तरीके से उपयोग करने बहुत सारे प्रासंगिक कारकों पर विचार करना होता है-

न्यायाधीशों को लगातार खुद को याद दिलाना होगा कि विवेक का उपयोग कानून द्वारा निर्देशित होना चाहिए, और प्राप्त परिस्थितियों में क्या उचित है- यह न्यायालय के ध्यान में रखना चाहिए कि जिन कुछ जघन्य अपराधों या क्रूर अपराधों से तरीके से किए गए मामलों में उच्च न्यायालयों ने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए बेहद नरम सजाएं दी हैं जो अंतरात्मा को झकझोर देती हैं- ऐसा नहीं होना चाहिए- यह लगाना अदालत का कर्तव्य है पर्याप्त सजा, अपेक्षित सजा लगाने के उद्देश्यों में से एक है समाज की सुरक्षा और सामूहिक विवेक के लिए एक वैध प्रतिक्रिया- सर्वोपरि मार्गदर्शक सिद्धांत यह होना चाहिए कि सजा आनुपातिक होनी चाहिए- न्यायिक नोटिस।

प्रत्यर्थीयों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 323, 326 और 447 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि बताई गई तारीख और समय पर, जब पीडब्लू4, पीडब्लू5 और पीडब्लू7 ट्रैक्टर की मदद से अपने खेत में कुछ कृषि गतिविधियाँ कर रहे थे, आरोपी-प्रत्यर्थी नं. 1 तलवार से युक्त और अन्य आरोपी प्रत्यर्थी फ्लैथिस से युक्त होकर वहां आए और ट्रैक्टर को

रोका और जब पीडब्लू4 और पीडब्लू6 ने ट्रैक्टर के चालक का बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन पर अपने हथियारों से हमला कर दिया। अभियुक्त-प्रत्यर्थी नं. 1 ने पीडब्लू4 पर तलवार से हमला किया और उसका बायां हाथ कलाई से काट दिया। घायलों को जी अस्पताल ले जाया गया और पीडब्लू5 द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी-प्रत्यर्थी संख्या 1 को आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया तथा 3000/-रुपये के जुर्माने के साथ 5 साल के लिए कठोरतम की सजा सुनाई। और आईपीसी की धारा 326 के तहत 4 साल की सश्रम कारावास और 2000/-रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। उन्हें आईपीसी की धारा 323/149 के तहत भी दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। अन्य आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 307/149 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया और 1000/- रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की सजा सुनाई गई। अपील पर, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी नंबर 1 को धारा 308, 148, 447, 326 और 323/149 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया तथा पूर्व में भुगती हुई सजा सुनाई यानी 7 दिनों के कारावास और 50000/-रुपये का जुर्माना। उच्च न्यायालय ने अन्य आरोपी उत्तरदाताओं को भी धारा 324/149, 147, 447 और 323 आईपीसी के तहत अपराध में दोषी ठहराया, लेकिन उनमें से कुछ के संबंध में सजा को पहले ही पूरी हो चुकी अवधि तक सीमित कर दिया और दूसरों को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 और 12 के तहत रिहा कर दिया। आरोपी प्रतिवादियों में से दो को

15000/-रुपये का जुर्माना प्रत्येक व्यथित को देने का निर्देश दिया गया। पीडब्लू4 ने अपील दायर की।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित किया: 1.1. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की व्याख्या करते हुए, दो सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट हैं; सबसे पहले, एक पीड़ित पक्ष है, अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा सर्वोत्तम न्यायालय की शक्ति के माध्यम से अपील कर सकता है। भारत के संविधान की अनुच्छेद 136 सर्वोच न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ देता है जो अन्याय को दूर कर सकती है; और दूसरा, सजा बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा की गई अपील में आरोपी यह दलील दे सकता है कि वह बरी होने का हकदार है क्योंकि दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। एफ [पैरा 14] [900-डी-ई]

यूपी राज्य बनाम धर्मेंद्र सिंह और अन्य 1999 (3) सप्ल एससीआर 52 = (1999) 8 एससीसी 325; निहाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 1964 एससीआर 5-एआईआर 1965 एससी 26; चंद्रकांत पाटिल बनाम राज्य थ्रू सीबीआई 1998 (1) एससीआर 447 = (1998) 3 एससीसी 38; यू.जे.एस. चोपड़ा बनाम बॉम्बे राज्य 1955 एससीआर 94 =एआईआर 1955 एससी 633; राजस्थान राज्य बनाम किशन लाल 2002 (3) एससीआर 1066 (2002) 5 एससीसी 424; पी.एस.आर. साधनन्थम बनाम अरुणाचलम

और अन्य (1980) 3 एससीसी 141; और एशरसिंह बनाम अंद्र प्रदेश राज्य 2004(2) एससीआर 1180 (2004) 11 एससीसी 585- संदर्भ मे

1.2. मौजूदा मामले में, राज्य ने कोई अपील नहीं की है, लेकिन पीड़ित को विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद अपील दायर करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 कि धारा 377 (3) के सिद्धांत लागू होते हैं और संविधान का अनुच्छेद 136 व्यापक आयाम वाला है जिसमें सर्वोच न्यायालय को शक्तियाँ है । इस प्रकार देखा जाए तो यह न्यायालय, तथ्यों और परिस्थितियों के अनुकूल होने पर पर्याप्त सजा दे सकता है। [पैरा 15] [900-ई-जी]

2.1. जहां तक अभियुक्त-प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील का संबंध है, यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग भले ही विशेष रूप से धारा 313 में न लिया गया हो। इसे हमेशा आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों से एकत्र किया जा सकता है। [पैरा 16] [901-बी, सी]

विद्या सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1971 एससी 1857; सिकंदर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य 2010 ई (8) एससीआर 373 = (2010) 7 एससीसी 477; और राजस्थान राज्य बनाम मनोज कुमार (2014) 4 स्केल 724-संदर्भ में किया।

2.2. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा एक निष्कर्ष दिया गया है कि घटना के दिन, विवादित भूमि का कब्ज़ा पीडब्लू -4 और अन्य के पास था और आरोपी के पास उन्हें जबरन बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पीड़ित हथियारों से युक्त नहीं थे और शांतिपूर्वक अपनी कृषि गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जब आरोपी व्यक्ति हथियारों से युक्त होकर आए और उन पर हमला कर दिया। पीडब्लू-4, पीडब्लू6 और अन्य की चोट रिपोर्ट प्रदर्श में शामिल है। पी-17 से एक्सटेंशन तक। पी-19 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें चोटें आई थीं और पीडब्लू4 को लगी चोटें गंभीर प्रकृति की थीं। एच उपचार करने वाले डॉक्टर की राय के अनुसार अन्य पीड़ितों को लगी चोटें तेज हथियार के कारण लगी थीं। पर दूसरी ओर, हमलावरों की चोटें बिल्कुल साधारण प्रकृति की थीं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि बचाव पक्ष व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील को स्थापित करने में सक्षम है, न ही उक्त अधिकार से अधिक का सवाल उठता है। इसलिए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने घायल व्यक्तियों पर हमला किया था और उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 326 के तहत दोषसिद्धि को सही ढंग से दर्ज किया है। [पैरा 17] [901-एफ-जी; 902-ए-बी, सी, डी-ई]

3.1. हालाँकि, सजा कम करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी कारण नहीं बताया गया है। जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया

वह इसकी क्रूरता को स्पष्ट रूप से बयां करता है। अपराध की गंभीरता खुद बयां करती है। एक युवक का हाथ कलाई से कट गया है. प्रासंगिक समय में समाज में व्याप्त भय मनोविकृति को समझना होगा। उच्च न्यायालय ने सज़ा को घटाकर पहले ही पूरी हो चुकी अवधि यानी ऐसे अपराध के लिए सात दिन कर दिया, लेकिन इन पहलुओं पर विचार करने में विफल रहा और संभवतः महसूस किया कि जुर्माना राशि में वृद्धि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगी। [पैरा 28] [907-ई-एच]

शाम सुंदर बनाम पूरन और अन्य 1990 (1) पूरक। एससीआर 662 एआईआर 1991 एससी 8; मध्य प्रदेश राज्य बनाम नजब खान और अन्य (2013) 9 एससीसी 509; हजारा सिंह बनाम राज कुमार और अन्य (2013) 9 एससीसी 516; सेवक पेरुमल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य 1991 (2) एससीआर 711 = (1991) 3 एससीसी 471; महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1987 (2) एससीआर 710 = (1987) 3 एससीसी 80; मप्र राज्य वी. सलीम उर्फ चमारू और दूसरा 2005 (1) सप्ल. एससीआर 562 = (2005) 5 एससीसी 554; रावजी उर्फ राम चन्द्र बनाम राजस्थान राज्य 1995 (6) सप्ल। एससीआर 195 (1996) 2 एससीसी 175; कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा 2000 (2) एससीआर 761 = एआईआर 2000 एससी 1470; श्याम नारायण बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2013) 7 एससीसी 77; गुरु बसवराज बनाम कर्नाटक राज्य 2012 (8) एससीआर 189 =

(2012) 8 एससीसी 734; और रत्तीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। 2012 (3) एससीआर 496 = (2012) 4 एससी 516- संदर्भ में किया गया।

ए जमील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 (15) एससीआर 712 = (2010) 12 एससीसी 532-संदर्भित।

3.2. हालाँकि सज़ा का सवाल विवेक का विषय है, फिर भी उक्त विवेक का उपयोग अदालत द्वारा काल्पनिक और मनमौजी तरीके से नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक कारकों पर विचार करने पर बहुत मजबूत कारणों को उक्त विवेक के नरमतापूर्वक उपयोग के लिए आधार बनाना होगा। न्यायाधीशों को लगातार खुद को याद दिलाना होता है कि विवेक का उपयोग कानून द्वारा निर्देशित होना चाहिए, और प्राप्त परिस्थितियों में क्या उचित है। [पैरा 29 और 31] [908-बी-सी; 909-एफ-जी]

रामजी दयावाला एंड संस (पी.) लिमिटेड बनाम इन्वेस्ट इंपोर्ट 1981 (1) एससीआर 899 = एआईआर 1981 एससी 2085; और मैसर्स. एयरो ट्रेडर्स प्रा. लिमिटेड बनाम रविंदर कुमार सूरी एआईआर 2005 एससी 15 को डी को संदर्भित किया गया।

न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1921 संस्करण, पृष्ठ 114 बेंजामिन एन. कार्डोज़ो द्वारा-संदर्भित पुस्तक।

4.1. पर्याप्त सज़ा देना अदालत का कर्तव्य है, क्योंकि अपेक्षित सज़ा देने का एक उद्देश्य समाज की सुरक्षा और सामूहिक विवेक के प्रति एक

वैध प्रतिक्रिया है। सर्वोपरि मार्गदर्शक सिद्धांत यह होना चाहिए कि सजा आनुपातिक होनी चाहिए। सजा सुनाते समय यह अदालत की जिम्मेदारी है कि वह खुद को अपनी भूमिका और कानून के शासन के प्रति सम्मान की याद दिलाए। इसे तर्कसंगत न्यायिक विवेक को उजागर करना चाहिए न कि किसी व्यक्तिगत धारणा या नैतिक प्रवृत्ति को। [पैरा 32] जी [909-जी-एच; 910-ए-बी]

4.2. मौजूदा मामले में, जुर्माना राशि में वृद्धि या संहिता के तहत मुआवजा देना कानून में उचित जवाब नहीं होगा। स्पष्ट रूप से एच अपर्याप्त और अनावश्यक रूप से उदार वाक्य में हस्तक्षेप उचित हैवारंट, क्योंकि अदालत पीड़ित की पीड़ा और पीड़ा और अंततः, समाज की पुकार से अपनी आँखें बंद नहीं कर सकती। इसलिए, संतुलन बनाते हुए, यदि प्रत्यर्थी को बी ट्रायल जज द्वारा लगाए गए जुर्माने के अलावा दो साल के कठोर कारावास की सजा दी जाती है, तो न्याय का उद्देश्य सबसे अच्छा होगा। [पैरा 32] [910-डी-एफ]

4.3. इस न्यायालय के संज्ञान में आया है कि कुछ जघन्य अपराधों या क्रूर तरीके से किए गए अपराधों में उच्च न्यायालयों ने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए बेहद नरम सजाएं दी हैं जो अंतरात्मा को झकझोर देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए. [पैरा 33] [910-जी-एच]

4.4. नतीजतन, ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट द्वारा दर्ज की गई सजा बरकरार रखी जाती है और ट्रायल जज और हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि आरोपी-प्रत्यर्थी को 2 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने से. [पैरा 36] [911-सी-डी]

केस कानून संदर्भ

1999 (3) सप्ल.एससीआर 52	सन्दर्भ पैरा 10
1964 एससीआर 5	सन्दर्भ पैरा 10
1955 एससीआर 94	सन्दर्भ पैरा 10
2002 (3) एससीआर 10	सन्दर्भ पैरा 11
(1980) 3 एससीसी 141	सन्दर्भ पैरा 12
2004 (2) एससीआर 1180	सन्दर्भ पैरा 13
एआईआर 1971 एससी 1857	सन्दर्भ पैरा 16
2010 (8) एससीआर 373	सन्दर्भ पैरा 16
(2014) 4 स्केल	सन्दर्भ पैरा 16
1990 (1) पूरक एससीआर	सन्दर्भ पैरा 18
2013) 9 एससीसी 509	सन्दर्भ पैरा 19
(2013) 9 एससीसी 516	सन्दर्भ पैरा 19

1991 (2) एससीआर 711 संदर्भ में पैरा 20

1987 (2) एससीआर 710 संदर्भ में पैरा 21

2005 (1) पूरक एससीआर 562 संदर्भ में पैरा 22

1995 (6) पूरक। एससीआर 195 संदर्भ में पैरा 23

2000 (2) एससीआर 761 संदर्भ में पैरा 24

(2013) 7 एससीसी 77 संदर्भ में पैरा 25

2012 (8) एससीआर 189 संदर्भ में पैरा 26

2012 (3) एससीआर 496 संदर्भ में पैरा 27

2009 (15) एसआर 712 संदर्भ में पैरा 27

1981 (1) एससीआर 899 संदर्भ में पैरा 30

एआईआर 2005 एससी 15 संदर्भ में पैरा 31

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 942/2014

उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर के एसबीसीआरएल संख्या 455/1984 में दिनांक 2 जुलाई, 2009 के निर्णय और आदेश से।

सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन, मनीष शर्मा, नवदीप सिंह, ख़ुशबू जैन, प्रतिभा जैन अपीलार्थी की ओर से।

रत्नाकर दास, डी के ठाकुर, सुशील शर्मा, डॉ वी पी अप्पन प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायाधिपति दीपक मिश्रा जे.

1. विशेष याचिका द्वारा प्रस्तुत अपील जो कि पीड़ित द्वारा कि गयी, अपील का मुख्य बिंदु यह था कि क्या राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खंडपीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी-आरोपी की दोषसिद्धि जो कि आईपीसी की धारा 307 के तहत थी, जिसे धारा 308 आईपीसी में परिवर्तित किया और धारा 148, 147, 326 और 323 आईपीसी के साथ पठित धारा 149 आईपीसी के तहत सजा को बरकरार रखते हुए सजा की अवधि को सात दिनों तक सीमित करना उचित है जिसे प्रत्यर्थी पहले ही भुगत चुका है और साथ ही 50,000/- रूपये का जुर्माना लगाना और, जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

2. तथ्यात्मक अनुमान, जैसा कि अप्राप्य है, यह है कि 19.7.1982 को लगभग 3.30 बजे जब सुमेर सिंह, पीडब्लू-4, जनक सिंह, पीडब्लू-5, और उनके छोटे भाई जय सिंह, पीडब्लू-7, ने एक अन्य व्यक्ति से एक ट्रैक्टर लिया था, अपने खेत में कुछ कृषि कार्य कर रहा था, आरोपी व्यक्ति सूरजभान सिंह, भंवर सिंह, विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह और पृथ्वी राज उर्फ पप्पू हथियारों से लैस होकर खेत में पहुंचे। आरोपी सूरजभान सिंह के पास

तलवार थी और अन्य आरोपियों के पास लाठियां थीं। खेत में आने पर, आरोपियों ने ट्रैक्टर रोक दिया और सुमेर सिंह, पीडब्लू-4, और मूल सिंह, पीडब्लू-6, ट्रैक्टर के चालक का बचाव करने आए। उस समय, आरोपी विक्रम सिंह ने मूल सिंह, पीडब्लू-6 पर लाठी से वार किया और सूरजभान ने मूल सिंह, पीडब्लू-6 की बायीं कोहनी पर तलवार से चोट पहुंचाई। इसके बाद जब उसने सुमेर सिंह के सिर पर तलवार से वार किया तो उसने बचाव में अपना हाथ आगे कर दिया, जिससे तलवार बाएं हाथ की कलाई पर लगी, जिससे हाथ कलाई से कट गया और सुमेर सिंह बेहोश होकर गिर गया। जैसा कि वर्णन में आगे दिखाया जाएगा, आरोपी व्यक्तियों ने अन्य लोगों पर हमला किया और वहां से चले गए। जय सिंह, पीडब्लू-7, और ट्रैक्टर के चालक ने घायल व्यक्तियों को राजगढ़ अस्पताल ले गए जहां उन्हें भर्ती कराया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट जनक सिंह, पीडब्लू-5 द्वारा दर्ज की गई और एफआईआर के आधार पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 323, 326 और 447 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

3. आपराधिक कानून लागू होने के बाद, जांच शुरू हुई और अंततः, आरोप-पत्र विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा गया, जिसने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया। अभियुक्तगणों ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि भूमि विवाद के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। ऐसी याचिका के कारण, मामले की सुनवाई विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2, अलवर द्वारा की गई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 24

गवाहों की जांच की और 37 दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाया, जिन्हें प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया है। बचाव पक्ष ने अपनी दलील के समर्थन में दो गवाहों से पूछताछ की और कुछ दस्तावेज प्रदर्शित किये।

4. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की सराहना करते हुए सूरजभान सिंह को आईपीसी की धारा 307 के तहत पांच साल के कठोर कारावास और 3000/- रुपये के जुर्माने की सजा दी और डिफ़ॉल्ट रूप से एक साल के कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। धारा 447 आईपीसी के तहत तीन माह का कठोर कारावास, धारा 326 आईपीसी के तहत चार साल का कठोर कारावास और 2,000/- रुपये का जुर्माना और अन्यथा की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास और धारा 323/149 आईपीसी के तहत तीन महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। जहां तक अन्य आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् पृथ्वी राज उर्फ पप्पू, सुरेंद्र सिंह, विक्रम सिंह और भंवर सिंह का संबंध है, उनमें से प्रत्येक को आईपीसी की धारा 147 के तहत छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, धारा 447 आईपीसी के तहत कठोर सजा भुगतनी पड़ी । धारा 307/149 आईपीसी के तहत तीन माह का कारावास, धारा 307/149 आईपीसी के तहत तीन साल का कठोर कारावास और 1000/- रुपये का जुर्माना भरना होगा, जुर्माना न भरने पर एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास और धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दंडित किया

जाएगा, छह महीने के लिए कठोर कारावास, इस शर्त के साथ कि सभी सजाएं एक साथ होंगी।

5. उपरोक्त फैसले और सजा से दुखी होकर आरोपी व्यक्तियों ने 1984 की आपराधिक अपील संख्या 455 दायर की और उच्च न्यायालय ने, जहां तक सूरजभान सिंह का सवाल है, उसे धारा 308, 148, 447, 326 और 323/149 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया। धारा 149 आईपीसी में उसे सात दिन की कैद की सजा सुनाई, जो वह पहले ही भुगत चुका था और 50,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जहां तक अन्य अभियुक्तों-अपीलकर्ताओं का सवाल है, उच्च न्यायालय ने उन्हें आईपीसी की धारा 324/149,147, 447 और 323 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया और उनकी उम्र को देखते हुए, सजा को कुछ के संबंध में पहले ही पूरी हो चुकी अवधि तक सीमित कर दिया और उनमें से कुछ अपराधियों को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 और 12 के तहत रिहा कर दिया। जहां तक आरोपी-अपीलकर्ता पृथ्वी राज उर्फ पप्पू और विक्रम सिंह का सवाल है, उन पर 15,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि सभी अभियुक्तों को जुर्माने की राशि तीन महीने के भीतर इस शर्त के साथ जमा करानी होगी कि वह राशि घायल सुमेर सिंह को दी जाएगी और जुर्माने की राशि जमा करने में विफल रहने पर दो साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

6. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुशील कुमार जैन और प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रत्नाकर दाश को सुना गया यहाँ यह ध्यान देने वाला तथ्य है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 की इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई जिससे उसके विरुद्ध अपील समाप्त हो जाती है। शुरुआत में, हमें यह दर्ज करना चाहिए कि श्री जैन ने सूरजभान सिंह को अपर्याप्त सजा देने तक ही अपनी दलीलें सीमित रखी हैं और हम ऐसा सोचने के इच्छुक हैं, यह सही भी है। आईपीसी की धारा 326 के तहत सजा को घटाकर सात दिन करने की न्यायोचितता की आलोचना करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जैन ने तर्क दिया कि इस तरह के उदार चित्रण में विशेष रूप से उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनके तहत अपराध किया गया था और अपराध की गंभीरता यह आपराधिक न्याय व्यवस्था प्रणाली का उपहास है क्योंकि पीड़ित की दुर्दशा, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट लगी है, ने अपने बाएं हाथ का उपयोग स्थायी रूप से खो दिया है। इसके अलावा, श्री जैन का मानना है कि इस तरह की अपर्याप्त सजा देना न्याय का मखौल है और किसी भी विशेष लक्षण और परिस्थितियों के अभाव में सामूहिकता पर इसका प्रभाव न केवल बेहद दर्दनाक है, बल्कि इसे नष्ट करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा। कानून के शासन का तानाबाना. विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि ऐसे मामले में केवल मुआवजा देने से न्याय

का उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत एक व्यवस्थित समाज का परिवेश नष्ट हो जाता है।

7. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डैश ने अपनी बारी में प्रतिपादित किया है कि दर्ज की गई सजा पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और वास्तव में, यदि आरोपी व्यक्तियों ने जिस तथ्य का पालन किया है, उसे ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों की उचित सराहना की गई होती। निजी बचाव का उनका अधिकार, मामला दोषमुक्ति में समाप्त हो जाता। उनका आग्रह है कि यह मानते हुए कि उन्होंने निजी बचाव के अधिकार का उल्लंघन किया है, तब भी अपराध आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध में परिवर्तित हो जाएगा और उस पृष्ठभूमि में, सजा को पहले से ही पूरी की गई अवधि तक सीमित किया जा सकता है। न्यायसंगत और पर्याप्त सजा की अवधारणा पर नाराजगी को आमंत्रित नहीं किया है। उनका आग्रह है कि घटना बहुत पहले घट चुकी थी; और कब्ज़े को लेकर मतभेद था और इसके अलावा अंतराल अवधि में रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि अभियुक्त किसी भी आपराधिक अपराध में शामिल था और इसलिए, सजा के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. सबसे पहले हम श्री डैश की दलील को ध्यान में रखते है कि क्या घायल द्वारा की गई अपील में दोषी अपनी सजा की कानूनी वैधता पर

सवाल उठा सकता है। इस संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") की धारा 377(3) का संदर्भ उपयुक्त होगा। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"377. सज़ा के ख़िलाफ़ राज्य सरकार द्वारा अपील.-(1)

.....

(2) .....

(3) जब अपर्याप्तता के आधार पर सजा के खिलाफ अपील दायर की गई है, तो उच्च न्यायालय आरोपी को ऐसी वृद्धि के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर देने के अलावा सजा नहीं बढ़ाएगा और कारण बताते समय, आरोपी सजा बढ़ा सकता है। उसे बरी करने या सजा कम करने की गुहार लगाएं।

9. संहिता की धारा 386 , प्रासंगिक होने के कारण निम्नलिखित है:-

386. अपीलीय न्यायालय की शक्ति- ऐसे रिकॉर्ड का अवलोकन करने और अपीलकर्ता या उसके वकील को सुनने के बाद, यदि वह उपस्थित होता है, और लोक अभियोजक यदि वह उपस्थित होता है, और धारा 377 या धारा 378 के तहत अपील के मामले में, यदि अभियुक्त उपस्थित होता है,

तो अपीलीय न्यायालय, यदि वह मानता है कि हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, अपील खारिज कर सकता है, या-

(ए) किसी आदेश या बरी किए जाने की अपील में, ऐसे आदेश को उलट दें और निर्देश दें कि आगे की जांच की जाए, या आरोपी पर फिर से मुकदमा चलाया जाए या मुकदमा चलाया जाए, जैसा भी मामला हो, या उसे दोषी पाया जाए और सजा दी जाए उसे कानून के अनुसार;

(बी) किसी दोषसिद्धि की अपील में-

(i) निष्कर्ष और सजा को उलट सकता है और आरोपी को बरी कर सकता है या आरोपमुक्त कर सकता है, या उसे ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पुनः मुकदमा चलाने का आदेश दे सकता है या मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है, या

(ii) निष्कर्ष को बदलना, वाक्य को बरकरार रखना, या

(iii) निष्कर्ष को बदलने के साथ या उसके बिना, वाक्य की प्रकृति या सीमा, या प्रकृति और सीमा को बदल दें, लेकिन ऐसा नहीं कि समान को बढ़ाया जा सके;

(सी) सजा बढ़ाने की अपील में-

(i) निष्कर्ष और सजा को उलट सकता है और आरोपी को बरी कर सकता है या आरोपमुक्त कर सकता है या उस पर अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोबारा मुकदमा चलाने का आदेश दे सकता है, या

(ii) वाक्य को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष में बदलाव करें, या

(iii) निष्कर्ष को बदलने के साथ या उसके बिना, वाक्य की प्रकृति या सीमा, या प्रकृति और सीमा को बदल दें, ताकि उसे बढ़ाया या घटाया जा सके;

(डी) किसी अन्य आदेश से अपील में, ऐसे आदेश को बदल दें या उलट दें;

(ई) कोई संशोधन या कोई परिणामी या आकस्मिक आदेश देना जो उचित या उचित हो;

बशर्ते कि सजा तब तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि आरोपी को ऐसी वृद्धि के खिलाफ कारण बताने का अवसर न मिल जाए:

बशर्ते कि अपीलीय न्यायालय उस अपराध के लिए अधिक सजा नहीं देगा जो उसकी राय में आरोपी ने किया है, जितना दिया जा सकता था।

उस अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अपील के तहत आदेश या सजा पारित की जाती है।रण, नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:

10. धारा 377(3) और इसका प्रभाव और विशेष अनुमति के अनुदान के बाद की गई अपील में आवेदन पर यूपी राज्य बनाम धर्मेंद्र सिंह और अन्य[1] में विचार किया गया था, जिसमें दो-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि उक्त प्रावधान का अवलोकन किया जाएगा। यह दर्शाता है कि यह केवल तभी लागू होता है जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष होता है और यह इस न्यायालय पर लागू नहीं होता है जब संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सजा बढ़ाने की अपील की जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संहिता की धारा 379 के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, आपराधिक मामलों में इस न्यायालय में अपील संहिता के तहत प्रदान नहीं की जाती है। आगे यह देखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में अपील संहिता के तहत वैधानिक अपील के समान नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यह न्यायालय अपील की एक नियमित अदालत नहीं है जिसमें एक अभियुक्त अपील कर सकता है। अधिकार के रूप में दृष्टिकोण. यह एक असाधारण क्षेत्राधिकार है जो केवल असाधारण मामलों में ही प्रयोग किया जा सकता है जब यह न्यायालय संतुष्ट हो कि उसे न्याय के गंभीर पतन को रोकने के

1 (1998) 8 एससीसी 325

लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, जैसा कि साक्ष्य की सराहना में केवल त्रुटि से अलग है। आगे बढ़ते हुए अदालत ने कहा:

"इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, यह न्यायालय नीचे की अदालतों पर लागू प्रक्रिया के नियमों से बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल अपने विवेक से सीमित है (निहाल सिंह बनाम पंजाब राज्य देखें)। मामले के उस दृष्टिकोण से, हमारी राय है कि की धारा 377(3) संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील पर लागू नहीं होती है।

इसके बाद, न्यायालय ने इस संदर्भ में चंद्रकांत पाटिल बनाम सीबीआई जरिये राज्य में निर्भर होकर और यूजेएस चोपड़ा बनाम बॉम्बे राज्य के निर्णय को अलग किया और इस प्रकार रखा गया: -

"इसका मतलब यह नहीं है कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील के निपटान के लिए एक प्रक्रिया तैयार करते समय संहिता की धारा 377(3) के तहत संहिता में पाए गए सिद्धांतों के अनुरूप सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखेगा। इसके अलावा इस न्यायालय में आपराधिक अपीलों के निपटान के लिए लागू

सर्वोच्च न्यायालय के नियमों से, न्यायालय संहिता में पाए गए ऐसे समान सिद्धांतों को भी अपनाता है ताकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रक्रिया को "निष्पक्ष प्रक्रिया" बनाया जा सके।''

आखिरकार, अदालत ने प्रत्यर्थी को संहिता की धारा 377(3) में पाए गए अनुरूप प्रावधान को अपनाकर सजा बढ़ाने के लिए यूपी राज्य द्वारा दायर अपील में बरी करने के लिए बहस करने के लिए दोषी ठहराया।

11. राजस्थान राज्य बनाम किशन लाल[2] में उक्त निर्णय संदर्भ में करते हुए। न्यायालय ने सोचा कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां उसे विद्वान न्याय मित्र को प्रत्यर्थी को बरी करने के लिए बहस करने की अनुमति देनी चाहिए और अंततः, दोषसिद्धि के फैसले को उलट दिया और प्रत्यर्थी को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

12. इस समय, पीएसआर साधननथम बनाम अरुणाचलम और अन्य में संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी है। उक्त मामले में, याचिकाकर्ता, एक आरोपी, को मृतक के भाई द्वारा दी गई विशेष अनुमति के माध्यम से अपील में दोषी ठहराया गया था, जो पहला मुखबिर भी नहीं था। दोषी-याचिकाकर्ता ने इस आधार पर दोषसिद्धि को खारिज करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की कि

---

2 (2002) 5 एससीसी 424

कार्यवाही अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक थी। संविधान पीठ ने उसी पर विचार करते हुए कहा कि हालांकि अनुच्छेद 136 एक प्रावधान नहीं देता है। किसी पक्ष को स्पष्ट शब्दों में अपील करने का अधिकार, फिर भी यह सर्वोच्च न्यायालय को उपयुक्त मामलों में हस्तक्षेप करने की व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। विवेकाधीन आयाम विचारणीय है लेकिन यह न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। बड़ी पीठ ने इस प्रकार कहा: -

> "हमारे विचार में, ऐसा होता है। अनुच्छेद 136 एक विशेष क्षेत्राधिकार है। यह अवशिष्ट शक्ति है; यह अपने आयाम में असाधारण है, इसकी सीमा, जब यह अन्याय का पीछा करती है, तो आकाश ही है। यह न्यायालय कार्यात्मक रूप से अन्याय तक पहुंच कर खुद को पूरा करता है यह जहां भी है और यह शक्ति बड़े पैमाने पर सामान्य मामलों में अनुच्छेद 136 से प्राप्त होती है।"

न्यायालय ने इस बिंदु का आगे विश्लेषण करते हुए कहा कि:-

> "हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहां एक प्रक्रिया आवश्यक रूप से शिखर न्यायालय में निहित शक्ति में निहित है। यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। संस्थापक पिता

ने अनुच्छेद 136 की शर्तों में निर्विवाद रूप से इरादा किया था कि यह हमारे न्यायशास्त्र में उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित न्यायिक सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायाधीशों द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा।"

इसके बाद, बड़ी पीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"9. हम इस मुद्दे को थोड़ा अलग तरीके से देख सकते हैं। यदि अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 136 में को सूक्षम रूप से देखा जाए, तो निष्कर्ष यह निकलता है कि विशेष अनुमति याचिका पर निष्पक्ष प्रक्रिया अंकित होती है जिसे अदालत दे सकती है या अस्वीकार कर सकती है। जब बरी होने के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए एक प्रस्ताव दिया जाता है , यह न्यायालय उस कार्यवाही में शामिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खतरे की गंभीरता की सराहना करता है। यह मान लेना उचित है कि अनुच्छेद 136 के तहत याचिका पर विचार करते समय अदालत स्वतंत्रता के सवाल पर ध्यान देगी, जो व्यक्ति न्यायलय से इस तरह की याचिका की अनुमति चाहता है, उसका मकसद और उसका अधिकार क्षेत्र और महत्वपूर्ण कारक जो अदालत

को विशेष अनुमति देने के लिए राजी करते हैं। जब प्रक्रियात्मक परिस्थितियों और मानदंडों का यह परिदृश्य अनुच्छेद 136 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष प्रक्रिया का पर्याप्त रूप से उत्तर दिया गया है।

10. एक बार जब हम मान लेते हैं कि अनुच्छेद 136 एक समग्र प्रावधान है जो एक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है और, इस अद्वितीय क्षेत्राधिकार को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने के तथ्य से, उस शक्ति का प्रयोग करने की पद्धति, अस्पष्ट रूप से, प्रतिपादित होती है, तो याचिकाकर्ता की आपत्ति में और कुछ नहीं बचता है। न्यायलय विशेष अनुमति याचिका देने के लिए स्वतंत्र है और सुनवाई की आगामी प्रक्रिया अच्छी तरह से स्थापित है। इस प्रकार, शक्ति-सह-प्रक्रिया का एक अभिन्न प्रावधान है जो जीवन और स्वतंत्रता से वंचित करने को उचित ठहराने वाले अनुच्छेद 21 की इच्छा के अनुरूप है। "

13. उक्त सिद्धांत को ईशर सिंह बनाम ए.पी. राज्य में यह बताते हुए दोहराया गया है कि यह न्यायालय हितबद्ध निजी पक्षों के कहने पर उच्च

न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार कर सकता है, उन परिस्थितियों के लिए जब संहिता में किसी अधीनस्थ द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान नहीं करती है। इस परिस्थति मे अनुच्छेद 136 के तहत हितकारी पक्ष को इस न्यायालय की शक्ति के प्रश्न की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

14. विधि के उपरोक्त प्रतिपादन से दो सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट होते हैं; सबसे पहले, एक घायल जो एक पीड़ित पक्ष है, विशेष याचिका अनुमति द्वारा अपील कर सकता है और अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्ति व्यापक आयाम की है, यह अन्याय को तब दूर कर सकता है जब वह इसका गवाह हो और दूसरा, सजा में वृद्धि के लिए राज्य द्वारा की गई अपील में अभियुक्त दलील दे सकता है कि वह बरी होने का हकदार है क्योंकि दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है।

15. मौजूदा मामले में, राज्य ने कोई अपील नहीं की है, लेकिन पीड़ित पक्ष को याचिका दायर करने की प्राप्त करने अनुमति दी गई है। हम पहले ही कह चुके हैं कि संहिता के 377(3) के अनुरूप सिद्धांत लागू हैं और अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति व्यापक आयाम की है। इस प्रकार देखा जाए तो, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि यह न्यायालय, किसी पीड़ित की अपील पर विचार करते हुए, पर्याप्त सजा क्यों नहीं दे सकता, जबकि तथ्य

और परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं। लेकिन उससे पहले, अपेक्षित परीक्षण लागू करने के लिए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की सराहना करनी चाहिए कि क्या दोषसिद्धि की रिकॉर्डिंग अनुचित है, और क्या उच्च न्यायालय ने सजा को पहले से ही पूरी की गई अवधि तक सीमित करके पूरी तरह से गलती की है ।

16. वर्तमान में, पहले अंक पर वर्णन के लिए. जैसा कि पहले कहा गया है, श्री डैश का एकमात्र तर्क यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने व्यतिगत बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग किया और यह मानते हुए भी कि उन्होंने उस अधिकार को पार कर लिया है, उन्हें केवल कम अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता था। इसके विपरीत, श्री जैन तर्क देंगे कि संहिता की धारा 313 के तहत निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग के लिए कोई दलील नहीं दी गई। बयान और, किसी भी मामले में, अपीलकर्ताओं ने आरोपी व्यक्तियों को इतने जघन्य तरीके से अपराध करने के लिए उकसाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग भले ही संहिता की धारा 313 में विशेष रूप से न लिया गया हो, इसे हमेशा आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों से संग्रहण किया जा सकता है। उक्त स्थिति विद्या सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, सिकंदर सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य और राजस्थान राज्य बनाम मनोज कुमार में बताई गई है।

17. मौजूदा मामले में, ट्रायल कोर्ट ने माना है कि राजस्व, अपीलीय अधिकारी, अलवर के प्रदर्श पी4 निर्णय से यह निर्विवाद है कि विवादित खेत का निर्णय सुमेर सिंह, पीडब्लू-4 एवं जनक सिंह, पीडब्लू-5 के पक्ष में दिया गया तथा रिसीवर की ओर से इन व्यक्तियों को कब्जा दिये जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया। राम बिलास, पीडब्लू-15, पटवारी, ने राजस्व अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में भूमि का कब्जा दे दिया था और यह रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य से स्पष्ट है। यह प्रमाणित है कि सहायक कलेक्टर, राजगढ़ ने रिसीवर से इस भूमि पर कब्जा कर लिया और इसे 14.4.1982 को सुमेर सिंह को सौंप दिया। एक निष्कर्ष दिया गया है कि घटना के दिन, यानी 19.7.1982 को कब्जा सुमेर सिंह, पीडब्लू-4, और अन्य के पास था और आरोपी को उन्हें जबरन बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं था। जो भी हो, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि जब आरोपी व्यक्ति हथियारों से युक्त होकर आये और उन पर हमला किया तो पीड़ित हथियारों से युक्त नहीं थे और शांतिपूर्वक अपनी कृषि गतिविधियाँ कर रहे थे। सुमेर सिंह, पीडब्लू-4, मूल सिंह और उमराव सिंह की चोट रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 से प्रदर्श पी-19 तक यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें चोटें आई थीं और सुमेर सिंह को लगी चोटें गंभीर प्रकृति की थीं। जैसा कि इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि मूल सिंह और उमराव सिंह को लगी चोटें धारदार हथियार से लगी थीं। प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डैश का तर्क होगा कि आरोपी व्यक्तियों को भी चोटें

आई थीं और इससे पता चलता है कि वे कब्ज़ा कर रहे थे और अपने अधिकार का बचाव करते समय एक लड़ाई हुई थी जो व्यतिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग स्थापित करती है और संभवतः इससे अधिक हो जाती है। चोट रिपोर्ट की जांच करने पर ऐसा सही प्रतीत होता है कि चोटें बिल्कुल साधारण प्रकृति की थीं। घायल व्यक्तियों के कब्जे और आरोपी व्यक्तियों को लगी चोटों की प्रकृति के संबंध में साक्ष्य के आधार पर दर्ज किए गए निष्कर्ष के संबंध में, यह नहीं कहा जा सकता है कि बचाव प्रयोग के अधिकार की दलील को स्थापित करने में सक्षम था। निजी प्रतिरक्षा के मामले में, उक्त अधिकार से अधिक का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने घायल व्यक्तियों पर हमला किया था और उच्च न्यायालय ने धारा 326 आईपीसी के तहत प्रत्यर्थी के खिलाफ दोषसिद्धि को सही ढंग से दर्ज किया है।

18. अगला प्रश्न जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या आईपीसी की धारा 326 के तहत हुई चोटों के संबंध में अपराध के लिए पर्याप्त सजा दी गई है। श्याम सुंदर बनाम पूरन और अन्य" में, उच्च न्यायालय ने आरोपी-अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 304 भाग-I के तहत दोषी ठहराया था और जुर्माना बढ़ाते हुए सजा को पहले ही काट ली गई कारावास की अवधि यानी छह महीने तक कम कर दिया था। उस संदर्भ में, न्यायालय की राय थी कि दी गई सज़ा अपर्याप्त थी। आगे बढ़ते हुए इस प्रकार राय दी गई है:-

इस तरह की सजा देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई विशेष कारण नहीं दिया गया है। किसी विशेष अपराध के लिए सजा तय करते समय अदालत को अपराध की प्रकृति, जिन परिस्थितियों में यह किया गया था, अपराधी की डिग्री विचार-विमर्श को ध्यान में रखना चाहिए।"। सजा का माप अपराध की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा इतनी गंभीर और पूरी तरह से अपर्याप्त प्रतीत होती है कि इसमें न्याय की विफलता शामिल है। हमारी राय है कि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए न्याय, सज़ा बढ़ानी होगी। इतना कहने के बाद अदालत ने सज़ा को पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास में बढ़ा दिया।

19. सेवका पेरुमल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य में, महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य में निर्णय का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त सजा देने की अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी, जिससे कानून की प्रभावकारिता में जनता का विश्वास कमजोर होगा और समाज गंभीर खतरों के तहत लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि अदालतें पीड़ितों की रक्षा नहीं करती हैं, तो पीड़ित व्यतिगत प्रतिरक्षा का सहारा लेंगे और इसलिए, प्रत्येक अदालत का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से यह निष्पादित या प्रतिबद्ध किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे|

20. एमपी राज्य बनाम सलीम उर्फ चमारू और अन्य में, न्यायालय ने राय दी कि सजा देने का उद्देश्य समाज की रक्षा करना और अपराधी को रोकना होना चाहिए जो कानून का स्वीकृत उद्देश्य है। इसने आगे फैसला सुनाया कि यह है, उम्मीद है कि अदालतें सजा प्रणाली का संचालन करेंगी ताकि ऐसी सजा दी जा सके जो समाज की अंतरात्मा को दर्शाती हो और सज़ा की प्रक्रिया वहां सख्त होनी चाहिए जहां यह होनी चाहिए।

21. रावजी उर्फ राम चंद्र बनाम राजस्थान राज्य में न्यायालय ने सामाजिक संदर्भ में पर्याप्त सजा देने की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए इस प्रकार कहा: -

10. यदि उस अपराध के लिए उचित दंड नहीं दिया गया जो न केवल व्यक्तिगत पीड़ित के खिलाफ बल्कि उस समाज के खिलाफ भी किया गया है जिससे अपराधी और पीड़ित है, तो अदालत अपने कर्तव्य में असफल होगी। किसी अपराध के लिए दी जाने वाली सज़ा अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह उस अत्याचार और क्रूरता के अनुरूप होनी चाहिए जिसके साथ अपराध किया गया है, अपराध की विशालता सार्वजनिक घृणा की गारंटी देती है और इसे "समाज की पुकार का जवाब देना चाहिए" अपराधी के खिलाफ न्याय के लिए"। हमारे विचार में, यदि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए निरर्थक और क्रूर हत्याओं के लिए सबसे अधिक निवारक

सज़ा नहीं दी गई है, तो निवारक सज़ा का मामला अपनी प्रासंगिकता खो देगा।

22. कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पर्याप्त सजा देने के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि समाज की सुरक्षा और अपराधी को रोकते हैं । यह कानून का स्वीकृत उद्देश्य है और इसे उचित सजा देकर हासिल किया जाना आवश्यक है और सजा सुनाते समय अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे सजा के सवाल से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करें और अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा देने के लिए आगे बढ़ें। .

23. जमील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 308 के तहत दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल के कठोर कारावास से दंडित किया था। अपील में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई। जब तक इस न्यायालय द्वारा मामले पर विचार किया गया, अपीलकर्ता पहले ही आठ महीने की हिरासत में रह चुका था। सजा को कम करते हुए, न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

> "15. सजा प्रणाली को संचालित करने में, कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक तंत्र या निवारण को अपनाना चाहिए। चतुराई से मॉड्यूलेशन द्वारा, सजा प्रक्रिया को जहां यह होना चाहिए वहां कठोर होना

चाहिए, और इसमें संयमित होना चाहिए जहां आवश्यक हो वहां दया करें। प्रत्येक मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, जिस तरीके से इसकी योजना बनाई गई और प्रतिबद्ध किया गया, अपराध करने का मकसद, अभियुक्त का आचरण, हथियारों की प्रकृति प्रयुक्त और अन्य सभी उपस्थित परिस्थितियाँ प्रासंगिक तथ्य हैं जो विचार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी।

16. प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे निष्पादित या प्रतिबद्ध किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे। सजा सुनाने वाली अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे सजा के सवाल से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करें और अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा देने के लिए आगे बढ़ें।"

24. श्याम नारायण बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) में, यह फैसला सुनाया गया है कि मुख्य रूप से यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी भी अपराध के लिए सजा देने का एक सामाजिक लक्ष्य होता है। अपराध की प्रकृति और अपराध करने के तरीके को ध्यान में रखते हुए सजा दी जानी चाहिए। सजा देने का मूल उद्देश्य इस सिद्धांत पर आधारित है कि

अभियुक्त को यह एहसास होना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए अपराध ने न केवल उसके जीवन में बल्कि सामाजिक ताने-बाने में भी दरार पैदा की है। उचित सज़ा का उद्देश्य इसलिए बनाया गया है ताकि समाज में व्यक्ति जो अंततः सामूहिक रूप से गठित होते हैं, ऐसे अपराधों के लिए बार-बार पीड़ित न हों, क्योंकि यह एक निवारक के रूप में कार्य करता है। कोर्ट ने कहा, यह सच है कि, कुछ अवसरों पर, दोषी को के लिए खुद को सुधारने के अवसर दिए जा सकते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि किए गए अपराध और लगाए गए दंड के बीच आनुपातिकता का सिद्धांत होना चाहिए। ध्यान में रखा गया. आगे यह राय दी गई है कि इस जटिल अभ्यास को अंजाम देते समय, अदालत के लिए यह देखना अनिवार्य है कि अपराध का समग्र समाज पर प्रभाव और तत्काल सामूहिक पर इसके प्रभाव के साथ-साथ पीड़ित पर भी इसका असर होगा। .

25. गुरु बसवराज बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में, न्यायालय को सजा नीति के बारे में चर्चा करते हुए यह कहना पड़ा: -

> "33. ऐसा शायद ही कोई हो सकता है कि अपराध और सजा के बीच एक अनुपात होना चाहिए। यह देखना अदालत का कर्तव्य है कि अपराध करने और सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दी जाए। न्याय के लिए सामूहिक आवाज जिसमें

पर्याप्त सजा शामिल है, को हल्के से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।''

26. रत्तीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य[3] में हालांकि एक अलग संदर्भ में, यह कहा गया है कि:-

"64. ... समय बीतने के साथ आपराधिक न्यायशास्त्र ने पीड़ित विज्ञान पर जोर दिया है जो मूल रूप से अपराधी के साथ-साथ पीड़ित के दृष्टिकोण से एक मुकदमे की धारणा है। दोनों को सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है। कुछ देशों में पीड़ित को उचित सम्मान और सम्मान दिया जाता है | यह देखना अदालत का कर्तव्य है कि पीड़ित का अधिकार सुरक्षित रहे।"

27. मध्य प्रदेश राज्य बनाम नजब खान और अन्य में, राज्य ने उच्च न्यायालय के रूप में अपील दायर की थी, धारा 326 आईपीसी के साथ धारा 34 आईपीसी में सजा को बरकरार रखते हुए, सजा को पहले से ही पूरी की गई अवधि तक कम कर दिया था। यानी 14 दिन. उस संदर्भ में, न्यायालय ने कई अधिकारियों का उल्लेख करने और सिद्धांतों को दोहराने के बाद कहा कि सजा प्रणाली के संचालन में, कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक मशीनरी या निवारण को

3 (2012) 4 एससीसी 516

अपनाना चाहिए। प्रत्येक मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, जिस तरह से इसकी योजना बनाई गई और प्रतिबद्ध किया गया, अपराध करने का मकसद, अभियुक्त का आचरण, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति और अन्य सभी परिस्थितियाँ शामिल हैं। प्रासंगिक तथ्य जो विचार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। आगे यह देखा गया कि अपर्याप्त सजा देने में अनुचित सहानुभूति न्याय वितरण प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी और कानून की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास को कमजोर करेगी। प्रत्येक अदालत का यह कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे निष्पादित या प्रतिबद्ध किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे। उचित सज़ा देने पर विचार करते समय अदालतों को न केवल अपराध के पीड़ित के अधिकारों को बल्कि पूरे समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा कहने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दिया गया और ट्रायल जज की सजा को बहाल कर दिया गया, जिसके तहत उन्होंने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसी तरह के सिद्धांत को हजारा सिंह बनाम राज कुमार और अन्य में दोहराया गया है ।

28. तत्काल मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को उपरोक्त सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले पर गौर करने पर, हम पाते हैं कि इसमें कोई भी कारण नहीं बताया गया है। जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया वह इसकी क्रूरता को स्पष्ट रूप से बयां

करता है। अपराध की गंभीरता खुद बयां करती है। एक युवक का हाथ कलाई से कट गया है. प्रासंगिक समय में समाज में भय मनोविकृति किस प्रकार व्याप्त रही होगी, इसकी कल्पना करने के लिए सोलोमन की बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। यह समझ पाना मुश्किल है कि उच्च न्यायालय ने ऐसे अपराध के लिए सजा को पहले ही पूरी हो चुकी अवधि यानी सात दिन तक कम करते समय किस संभावित कारण की कल्पना या विचार किया होगा। संभवतः, उच्च न्यायालय को लगा कि जुर्माने की राशि बढ़ाने से न्याय मिलेगा, पीड़ित की शिकायत दूर होगी और सामूहिक रोना शांत होगा। हम ऐसा सोचने के इच्छुक नहीं हैं।

29. यहाँ यह बताना प्रतीत होता है कि यद्यपि सजा का प्रश्न विवेक का विषय है, फिर भी उक्त विवेक का उपयोग अदालत द्वारा काल्पनिक और मनमौजी तरीके से नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक कारकों पर विचार करने पर बहुत मजबूत कारणों को उक्त विवेक के उदार उपयोग के लिए आधार बनाना होगा। इसकी वजह यह है कि मार्मिक और अद्वितीय अभिव्यक्ति की गूंज, एक तरह से द नेचर ऑफ द ज्यूडिशियल प्रोसेस में बेंजामिन एन. कार्डोज़ो की चेतावनी है

न्यायाधीश स्वतंत्र होने पर भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। उसे अपनी खुशी के लिए कुछ भी नया नहीं करना है। वह अपने स्वयं के आदर्श की खोज में स्वेच्छा से घूमने वाला एक शूरवीर नहीं है सुंदरता या

अच्छाई की। उसे पवित्र सिद्धांतों से अपनी प्रेरणा लेनी है। उसे अनैच्छिक भावनाओं, अस्पष्ट और अनियंत्रित परोपकार के आगे झुकना नहीं है। उसे परंपरा द्वारा सूचित, सादृश्य द्वारा व्यवस्थित, प्रणाली द्वारा अनुशासित विवेक का प्रयोग करना है, और 'सामाजिक जीवन में व्यवस्था की मौलिक आवश्यकता' के अधीन।

30. इस संबंध में, हम रामजी दयावाला एंड संस (पी.) लिमिटेड बनाम इन्वेस्ट इंपोर्ट से एक उद्धरण उद्धृत कर सकते हैं :- "... जब यह कहा जाता है कि कोई मामला अदालत के विवेक के अंतर्गत है। सुस्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार, तर्क और निष्पक्ष खेल के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि सनक और सनक के अनुसार। 'विवेक', आर. बनाम विल्क्स में लॉर्ड मैन्सफील्ड ने कहा, ((1770) 98 ईआर 327), 'जब न्याय की अदालत में लागू होने का अर्थ है कानून द्वारा निर्देशित ठोस विवेक। इसे नियम द्वारा शासित किया जाना चाहिए, हास्य से नहीं; यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि कानूनी और नियमित होना चाहिए' (क्रेज़ ऑन स्टैच्यूट लॉ, 6वां देखें) एड., पी.

31. मैसर्स एयरो ट्रेडर्स प्रा. लिमिटेड बनाम रविंदर कुमार सूरी[4] में न्यायालय ने कहा: -

---

4 एआईआर 2005 एससी 15

"ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार "न्यायिक विवेक" का अर्थ है किसी न्यायाधीश या न्यायालय द्वारा परिस्थितियों में जो उचित है उसके आधार पर और कानून के नियमों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित निर्णय का प्रयोग; एक वादी होने पर कार्य करने या न करने की न्यायालय की शक्ति अधिकार के रूप में कार्य की मांग करने का हकदार नहीं है। "विवेकाधिकार" शब्द आवश्यक रूप से न्यायिक चरित्र के कार्य को दर्शाता है, और, जैसा कि न्यायिक रूप से प्रयोग किए गए विवेक के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, इसका तात्पर्य है एक कठोर और तेज़ नियम की अनुपस्थिति, और इसके लिए निर्णय के वास्तविक अभ्यास और उन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता होती है जो एक ठोस, निष्पक्ष और उचित निर्धारण करने के लिए आवश्यक हैं, और उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर विवेक हो सकता है ठीक से संचालित करें। (27 कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम पृष्ठ 289 देखें)। जब यह कहा जाता है कि अधिकारियों के विवेक के भीतर कुछ किया जाना है, तो कुछ कारण और न्याय के नियमों के अनुसार किया जाना है, न कि निजी राय के अनुसार; कानून के अनुसार और हास्य के अनुसार नहीं। यह केवल किसी मंत्री या प्रशासनिक

अधिकारी से अलग न्यायाधीश को उसके सामने लाए गए मामलों पर निर्णय देने के लिए क़ानून या नियमों द्वारा प्रदत्त कुछ छूट या स्वतंत्रता देता है।"

इस प्रकार, न्यायाधीशों को लगातार खुद को याद दिलाना होता है कि विवेक का उपयोग कानून द्वारा निर्देशित होना चाहिए, और प्राप्त परिस्थितियों में क्या उचित है।

32. विवेक के बारे में चर्चा करने के बाद, अब हम किसी अपराध के लिए सजा देते समय शक्ति के प्रयोग में के कर्तव्य पर उल्लेख करेंगे । पर्याप्त सज़ा देना अदालत का कर्तव्य है, क्योंकि अपेक्षित सज़ा देने का एक उद्देश्य समाज की सुरक्षा और सामूहिक विवेक के प्रति एक वैध प्रतिक्रिया है। लेज़र बीम की तरह मार्गदर्शक होने वाला सर्वोपरि सिद्धांत यह है कि सजा आनुपातिक होनी चाहिए। यह सामाजिक विवेक के प्रति कानून का उत्तर है। एक तरह से, यह उस समाज का दायित्व है जिसने बुराई पर अंकुश लगाने के लिए कानून की अदालत में विश्वास जताया है। सजा सुनाते समय यह न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह अपनी भूमिका और कानून के शासन के प्रति सम्मान की याद दिलाए। इसे तर्कसंगत न्यायिक विवेक को उजागर करना चाहिए न कि किसी व्यक्तिगत धारणा या नैतिक प्रवृत्ति को। लेकिन, यदि अंततः उचित सज़ा नहीं दी जाती है, तो सज़ा का बुनियादी व्याकरण ख़राब हो जाता है। कानून इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता;

समाज इसका सामना नहीं करता; और अंतःकरण की पवित्रता से उसे घृणा होती है। पुरानी कहावत "कानून किसी के अतीत का शिकार कर सकता है" को अशोभनीय तरीके से दफनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और दया के इंद्रधनुष को, बिना किसी समझ के, शासन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सच है कि उसका अपना स्थान है, लेकिन, सभी परिस्थितियों में, उसे पूरे आवास पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में पीड़ित आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है. हमें नहीं लगता कि जुर्माना राशि में वृद्धि या संहिता के तहत मुआवजा देना कानून में उचित उत्तर होगा। पैसा सर्वोपरि नहीं हो सकता. यह समस्त मुक्ति के लिए केंद्रीय भूमिका नहीं निभा सकता। स्पष्ट रूप से अपर्याप्त और अनावश्यक रूप से उदार सजा में हस्तक्षेप उचित वारंट है, क्योंकि न्यायालय पीड़ित की पीड़ा और पीड़ा और अंततः, समाज की पुकार के प्रति अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है। इसलिए, संतुलन बनाते हुए हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि न्याय का उद्देश्य सबसे अच्छा होगा यदि प्रत्यर्थी को विद्वान ट्रायल जज द्वारा लगाए गए जुर्माने के अलावा दो साल के कठोर कारावास की सजा दी जाए।

33. मामले से अलग होने से पहले हम यह कहने के लिए बाध्य हैं, बल्कि, दर्दनाक रूप से यह कहने के लिए बाध्य हैं कि इस न्यायालय के ध्यान में यह आया है कि कुछ जघन्य अपराधों या क्रूर तरीके से किए गए अपराधों में उच्च न्यायालयों ने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए

अत्यंत उदार वाक्य जो अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए. यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिसरो ने सदियों पहले क्या कहा था:-"यह वास्तव में कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट एक बोलने वाला कानून है, और कानून एक मूक मजिस्ट्रेट है।

34. कुछ दशक पहले फेलिक्स फ्रैंकफर्टर ने इस प्रकार कहा था न्यायिक कर्तव्य का सर्वोच्च अभ्यास किसी के व्यक्तिगत आकर्षण और उसके निजी विचारों को उस कानून के अधीन करना है जिसके हम सभी संरक्षक हैं -वे अवैयक्तिक दृढ़ विश्वास जो किसी समाज को सभ्य समुदाय बनाते हैं, न कि व्यक्तिगत शासन का शिकार।

35. हम उपरोक्त अनुस्मारक के साथ अलग होते हैं।

36. नतीजतन, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है, ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई सजा को बरकरार रखा जाता है और विद्वान ट्रायल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा को यहां ऊपर बताई गई सीमा तक संशोधित किया जाता है।

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा ढाका (आर.जे.एस.) यू.आई.डी. नं. आर.जे.00718 द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।